Daily Current Affairs

नोटा की प्रासंगिकता और सम्बद्ध मुद्दे

संदर्भ:-

- NOTA (None Of The Above) - उपरोक्त में से कोई नहीं। संभवतः सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में सबसे अधिक बहस वाले प्रावधानों में से एक है। यह मतदाताओं के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में उतारे गए उम्मीदवारों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर उपलब्ध एक विकल्प है।
- यह नकारात्मक मत नहीं है, बल्कि एक तटस्थ मत है जो मतदाताओं को उम्मीदवारों के उपलब्ध विकल्पों के साथ अपनी असहमति दर्ज करने की अनुमति देता है।
- वर्ष 2013 तक, अगर लोग इसी तरह का विकल्प चुनना चाहते थे, तो उन्हें चुनाव संचालन के नियम 49-ओ के तहत ऐसा करना पड़ता था।
- हालाँकि, इसमें मतदान केंद्र पर एक फ़ॉर्म भरना शामिल था, जिसका अर्थ था कि मतदाता को दी गई गोपनीयता से समझौता किया गया था।
- इसलिए, 2013 में पीयूसीएल नामक एक नागरिक अधिकार संगठन ने चुनावी प्रक्रिया में नोटा विकल्प को शामिल करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
- तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन) और संबंधित राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर नोटा का विकल्प शामिल करे।

ResultMitra

- 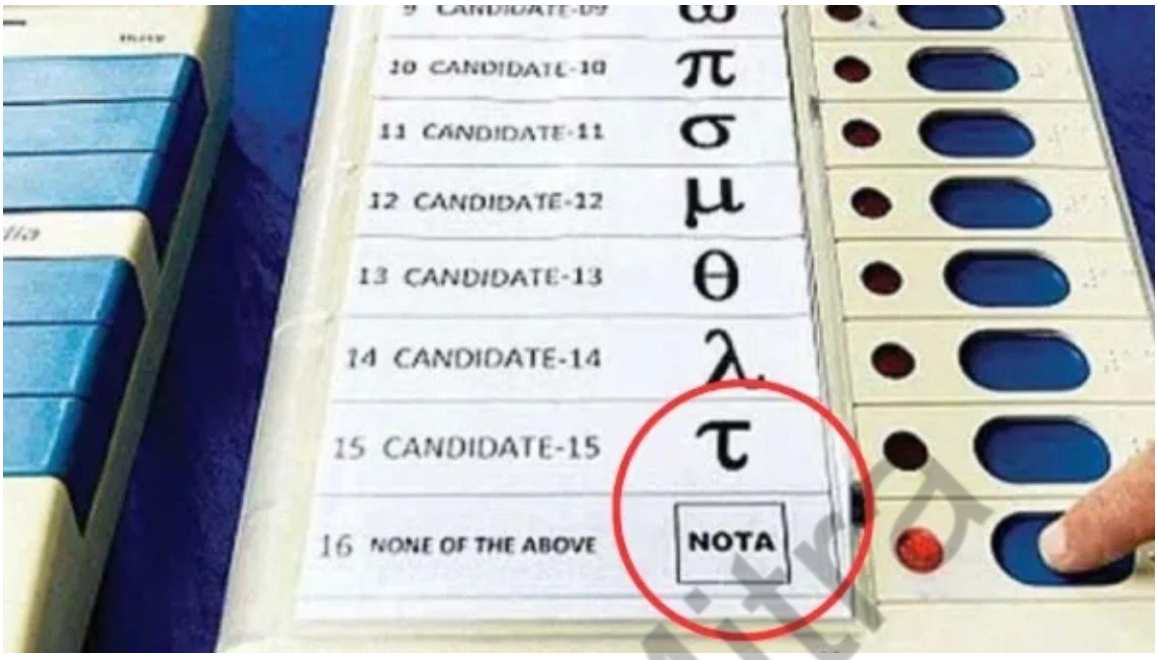

आखिर यह विकल्प इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या निष्पक्ष मतदाता मतदान से दूर नहीं रह सकते?

- अपितु मतदान से दूर रहने वाले सभी लोग जरूरी नहीं कि चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवारों को अस्वीकार या नापसंद करते हों। वे कई कारणों से मतदान नहीं कर सकते।
- साथ ही , नोटा अस्वीकृति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है।
- यद्यपि अस्वीकृति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतदाताओं की मांग नहीं सुनी जाना, सभी उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड होना या वित्तीय दुराचार के आरोप होना आदि।
- दूसरा, चुनाव से दूर रहने के बजाय नोटा का उपयोग करने से यह सुनिश्चित होता है कि वोट का दुरुपयोग या धोखाधड़ी वाला मतदान नहीं होगा।
- गौरतलब है कि नोटा विकल्प पहली बार 2013 में चार राज्यों - छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में लागू किया गया था।

भारतीय मतदाताओं पर नोटा का प्रभाव

- नोटा विकल्प चुनाव के परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता ।
- ईवीएम पर नोटा विकल्प का कोई चुनावी मूल्य नहीं है।
- यदि नोटा के लिए अधिकतम वोट पड़े तो भी शेष वोटों में से सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।
- नोटा वोट को अवैध या शून्य वोट माना जाता है ।
- हालांकि नोटा के गुण-दोषों को लेकर विशेषज्ञों और मतदाताओं में काफी मतभेद है।
- हाल ही में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि मौजूदा स्थिति में नोटा का केवल प्रतीकात्मक महत्व है और इसका किसी भी सीट के चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

Result Mitra

- उन्होंने कहा, "अगर किसी चुनाव में 100 में से 99 वोट नोटा को जाते हैं और उम्मीदवार को केवल एक वोट मिलता है, तो भी नोटा को नहीं बल्कि उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाएगा।"
- इस वर्ष अप्रैल में, एक याचिककर्ता (वक्ता शिव खेड़ा) द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की थी कि चुनाव आयोग नोटा को एक काल्पनिक चरित्र के रूप में देखे और उन निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश तय करे जहाँ नोटा को बहुमत मिलता है। साथ ही न्यायालय ने इस मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- गौरतलब है कि, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में नोटा को 1.29 करोड़ से अधिक वोट मिले हैं। एडीआर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्य और आम चुनावों में कुल मिलाकर नोटा पर डाले गए वोट 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत के बीच रहे हैं।

क्या नोटा एक संवैधानिक अधिकार या कर्तव्य है?

- इस मुद्दे पर भी दोनों पक्षों में मतभेद है।
- नोटा के पक्षधरों का तर्क है कि उनका मानना है कि यह मतदाताओं के लिए एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है।
- यह लोगों को उन उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का एक वास्तविक तरीका देकर चुनावों में भाग लेने की अनुमति देता है जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से, नोटा नागरिकों को अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का मौका देता है और राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार पेश करने के लिए प्रेरित करता है।
- नोटा की सहायता से मतदाताओं को दो भ्रष्ट उम्मीदवारों में से कमभ्रष्ट उम्मीदवार का चुनाव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपने मत का सद्पयोग कर सकेंगे।
- नोटा का अधिकार नागरिकों कोअधिक सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे बिना किसी भय केअयोग्य उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं।
- संजय पारीख (अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार "कुछ लोगों का तर्क है कि नोटा लागू होने से चुनाव खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन एक दागी उम्मीदवार जो भ्रष्टाचार और गलत कामों में लिप्त है, वह देश के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है।"
- दूसरी ओर, नोटा के आलोचकों का तर्क है कि यह नागरिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के संवैधानिक कर्तव्य को कमजोर कर सकता है। किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए वोट डालने के विपरीत, नोटा का चयन सीधे तौर पर किसी निर्वाचित अधिकारी के चयन में योगदान नहीं देता है।
- वर्तमान नियमों पर आधारित 'नोटा' केवल एक प्रतीकात्मक तथा महत्त्वहीन विकल्प है इससे चुनाव में जन भागीदारी का कोई औचित्य नहीं रहता।
- नोटा का विकल्प चुनकर मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने से परहेज़ कर रहे हैं जो उनकी ओर से शासन करेंगे।
- नोटा केवल नकारात्मक मताधिकार देता है। इससे चुनाव में उम्मीदवार की जीतया हार पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी कारण पूर्व चुनाव आयुक्त ने इसे दंतहीन विकल्प कहा है।
- नोटा का विकल्प तभी कारगर सिद्ध होगा, जब मतदाताओं को निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवारों को ख़ारिज करने का अधिकार मिलेगा।

नोटा को सशक्त करने के संदर्भ में किये गए प्रयास

- वर्ष 2018 में पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की थी जहाँ जीत का अंतर नोटा की कुल संख्या से कम है।

Result Mitra

- नोटा के स्थान पर 'अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार' (Right to Reject) मांगने के लिये मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
- वर्ष 2018 में महाराष्ट्र एवं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि यदि नोटा को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं तो उस विशेष सीट के लिये उक्त चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा और इस तरह के पद के लिये नए सिरे से चुनाव किया जाएगा।

निष्कर्ष

- चुनावों में नोटा के विकल्प को सार्थक बनाने के लिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलने की स्थिति में, चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए, साथ ही उल्लिखित उम्मीदवारों को अगले चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण को रोकने के लिए व्यापक चुनावी बदलाव की आवश्यकता है।
- मतदाताओं को नोटा के प्रभाव को समझाने के लिए, सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटा के बारे में मतदाताओं की समझ बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।

वर्ष 2024 में ला नीना वैश्विक मौसम को करेगा प्रभावित

चर्चा में क्यों?

- बीते माह, भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा भारत में आगामी मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगाया था, साथ ही अगस्त-सितंबर तक "अनुकूल" ला नीना स्थितियाँ बनने की उम्मीद है।
- अपितु भारतीय मौसम विभाग के एक अन्य हालिया बुलेटिन में बताया गया है कि इस साल की शुरुआत से अल नीनो की स्थिति कमज़ोर हो गई है।

एल नीनो और ला नीना

- एल नीनो (स्पेनिश में जिसका अर्थ है "छोटा लड़का") और ला नीना (स्पेनिश में जिसका अर्थ है "छोटी लड़की") जलवायु संबंधी घटनाएँ हैं जो महासागर-वायुमंडल की परस्पर क्रियाओं का परिणाम हैं, जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जल के तापमान को प्रभावित करती हैं, जिससे वैश्विक मौसम प्रभावित होता है।
- ये जटिल मौसम पैटर्न हैं, जो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण घटित होते हैं।
- ये अल नीनो-दक्षिणी दोलन (El Nino-Southern Oscillation- ENSO) चक्र की विपरीत अवस्थाएँ होती हैं।
- ENSO चक्र पूर्व-मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में महासागर एवं वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।
- अल नीनो और ला नीना की घटनाएँ आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती हैं, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलने वाली घटनाएँ वर्षों तक बनी रह सकती हैं।

अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) घटना की "उष्ण अवस्था" है।

- पृथ्वी के पूर्व-पश्चिम घूमने के कारण भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री के बीच बहने वाली सभी हवाएँ अपने प्रक्षेप पथ में तिरछी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में हवाएँ उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण-

Result Mitra

पश्चिम दिशा की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इसे कोरिओलिस प्रभाव के रूप में जाना जाता है।

- इसके कारण, इस वायु पेटी में हवाएँ (जिन्हें व्यापारिक हवाएँ कहा जाता है) भूमध्य रेखा के दोनों ओर पश्चिम की ओर बहती हैं।
- सामान्य समुद्री परिस्थितियों में, ये व्यापारिक हवाएँ दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर चलती हैं।
- समुद्र के ऊपर हवा की गति के परिणामस्वरूप अपवेलिंग के कारण समुद्र की सतह के नीचे ठंडा जल ऊपर उठता है और गर्म सतह के जल को विस्थापित करता है।
- कई बार, कमज़ोर व्यापारिक हवाएँ दक्षिण अमेरिका की ओर वापस चली जाती हैं और कोई अपवेलिंग नहीं होता।
- इस प्रकार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के साथ-साथ सामान्य से ज़्यादा गर्म समुद्री सतह का तापमान दर्ज किया जाता है, और इसे एल नीनो स्थितियों के उद्भव के रूप में जाना जाता है।
- वहीं ला नीना, अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) की "शीत अवस्था" होती है, यह पैटर्न पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाता है।
- अल नीनो की घटना जो कि आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है, के विपरीत ला नीना की घटनाएँ एक वर्ष से तीन वर्ष तक बनी रह सकती हैं।
- दोनों घटनाएँ उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती हैं।

आने वाली ला नीना वैश्विक मौसम को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?

- अल नीनो दक्षिणी दोलन और समुद्री जल के गर्म या ठंडे होने के कारण इस क्षेत्र में वायु परिसंचरण चक्र भी प्रभावित होता है। इससे पड़ोसी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है और भारतीय मानसून पर भी असर पड़ता है।
- पिछले वर्ष जून में शुरू हुआ अल नीनो का चलन काफी कमज़ोर हो गया है।
- इस वर्ष जून माह तक तटस्थ अल नीनो दक्षिणी दोलन स्थितियाँ बने रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद, ला नीना स्थितियाँ उभरने की उम्मीद है और इसका असर अगस्त माह से प्रभावी हो सकता है।

भारत पर ला नीना का प्रभाव

- सामान्य से अधिक बारिश के पूर्वानुमान के साथ मौसमी वर्षा, दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो कि 880 मिमी है।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर, शेष सभी क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक मौसमी वर्षा होने की उम्मीद है। साथ ही भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में नदी और शहरी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं।
- ला नीना वर्षों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में औसत मौसमी वर्षा कम होती है। इसलिए, इस वर्ष वहां जल भंडार में कमी हो सकती है।
- ला नीना वर्षों के दौरान, आमतौर पर आंधी-तूफान की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
- जुलाई और अगस्त माह के दौरान वर्षा ऋतु में कृषि संबद्ध गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं। हालांकि मौसम में बिजली और गरज के साथ होने वाली बारिश के कारण इन क्षेत्रों में मौत का उच्च जोखिम है।

ला नीना का विश्व पर प्रभाव

Result Mitra

- भारत की तरह इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और उनके पड़ोसी देशों में भी ला नीना वर्ष के दौरान अच्छी बारिश होती है। इस साल इंडोनेशिया में बाढ़ आ चुकी है।
- दूसरी ओर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में सूखा आम बात है, जहाँ सर्दियाँ सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट पर भारी वर्षा और बाढ़ आती है। दक्षिणी अफ़्रीका में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होती है।
- अटलांटिक महासागर पर तूफान की गतिविधि पर ENSO का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ला नीना वर्ष के दौरान, यहाँ तूफान की गतिविधि बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अटलांटिक महासागर ने ला नीना वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड 30 तूफान उत्पन्न किए।

जलवायु परिवर्तन का अल नीनो दक्षिणी दोलन पर प्रभाव

- भारत में, अल नीनो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा की मात्रा में कमी लाने तथा वर्तमान ग्रीष्म ऋतु की तरह उच्च तापमान और तीव्र गर्मी की लहरों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
- वर्ष 2020-2023 की अवधि में सदी की सबसे लंबी ला नीना घटना देखी गई।
- इसके बाद, अल नीनो दक्षिणी दोलन तटस्थ स्थितियाँ विकसित हुईं, जिससे जून 2023 तक एल नीनो का आगमन हुआ, जो पिछले वर्ष के दिसंबर से लगातार कमजोर हो रहा है। अपितु ला नीना में यह तेज बदलाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस तरह की जलवायवीय घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
- भू-वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र को प्रभावित करने वाला है।
- विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग प्रशांत महासागर पर औसत समुद्री स्थितियों को बदलने और अधिक एल नीनो घटनाओं को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार जलवायु परिवर्तन से एल नीनो और ला नीना से जुड़ी चरम मौसम और जलवायु घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति पर असर पड़ने की संभावना है।

भारत में वायु गुणवत्ता पर ला नीना का प्रभाव

- राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (बेंगलुरु) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (पुणे) के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया है, जिसके अनुसार भारत में वायु गुणवत्ता पर ला नीना का प्रभाव देखा जा सकता है।
- इस अध्ययन के अनुसार, यह पहली बार है कि भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता को ला नीना घटना से जोड़ा गया है - और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से भी, जो एल नीनो और ला नीना को और अधिक गंभीर बना रहा है।
- सामान्यतः उत्तर भारतीय शहरों (विशेषकर दिल्ली) में अक्टूबर से जनवरी माह के दौरान PM2.5 की सांद्रता बहुत अधिक होती है।
- हालाँकि, वर्ष 2022 की सर्दियों में इस सामान्य से काफी विचलन देखा गया।
- उत्तरी भारतीय शहर (दिल्ली सहित) सामान्य से अधिक स्वच्छ थे, जबकि पश्चिम और दक्षिण के शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में वायु की गुणवत्ता सामान्य से अधिक खराब थी।
- अध्ययन के अनुसार दिल्ली में PM2.5 की सांद्रता में लगभग 10% की कमी देखी गई। वहीं, मुंबई में सांद्रता में 30% की वृद्धि हुई, जबकि बेंगलुरु में 20% की वृद्धि दर्ज की गई।
- शोधकर्ताओं ने इस असामान्य व्यवहार की जांच शुरू की थी, तभी उन्हें ला नीना के संभावित प्रभावों का पता चला।

ResultMitra

- सभी ला नीना घटनाएं भारत में वायु परिसंचरण में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लातीं, लेकिन यह एक विशेष रूप से मजबूत घटना थी।
- वायु परिसंचरण पर प्रभाव ला नीना के तीसरे वर्ष में ही स्पष्ट हुआ। इसलिए, इसका संचयी प्रभाव हो सकता है।
- हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि अल नीनो भारत में वायु गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालेगा या नहीं।

Result Mitra